

SSD GD 2025

अक्सर बीच

\*POLITY\*

Class - 06

→ संवैधानिक उपायों का अधिकार  
(Right to constitutional remedies)

अनु०-32

डा० भीम राव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का  
हृदय और आत्मा कहा है।

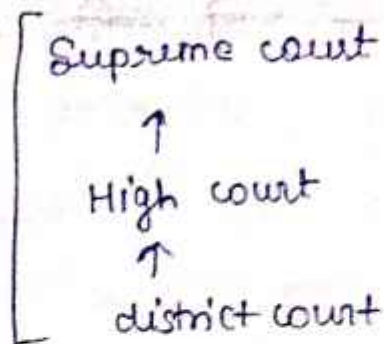
Art-32

Dr. Bhim Rao Ambedkar called it the heart and  
soul of the Indian constitution.

Art-32 ⇒ Supreme Court जैसा का अधिकार

Art-226 ⇒ High Court " " " " |

# Rojar with Ankit



पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा -

- ① बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) → व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाये।
  - ② परमादेश (Mandamus) → नौकर, → पुलिस अधिकारी
  - ③ प्रतिषेध (Prohibition) → सीटिन को निरस्तार
  - ④ उत्प्रेषण (Certiorari) तथा
  - ⑤ अधिकार पृच्छा (Quo warranto) → सीटिन का कर्तव्य है कि वह सीटिन को 24 घण्टे के अंदर 2 (within 2 hrs) मैजिस्ट्रेट समक्ष लेकर जाए। लेकिन मौलन ऐसा नहीं करता है।
- इसलिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण मौलन के खिलाफ जारी।

परमादेश (Mandamus) → हम आदेश देते हैं (we order)  
 → (किसके विरुद्ध जारी?) ⇒ सार्वजनिक अधिकारियों (Public officers)  
 ⇒ सरकार (Government)  
 जब ये लोग अपना कर्तव्य निभाने से मना करें। (अपना कार्य करने से मना करें) ⇒ पंचायत (Panchayat's) नगरपालिका (Municipality)  
 ⇒ निगम (Corporations)  
 ⇒ Superordinate courts (उच्चमिस्थ न्यायालय etc)

प्रतिषेध (Prohibition) → मना करना  
 → किसके विरुद्ध (against) जारी (issue)? ⇒ Subordinate courts (उच्चमिस्थ न्यायालय)



## Rojar with Ankit

उपेक्षा (Exception) → मगवा जेना

→ विरुद्ध (against) ⇒ Subordinate courts

प्रहूच गया  
district court

ex- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामला  
Protection of fundamental rights related matter

↓  
Supreme court / High court

अधिकार पृच्छा (Habeas corpus)

↓  
What's your authority? (आपका क्या अधिकार है?)

↓  
जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद (Public officer) के पद को अवैधानिक (illegal) तरीके से ग्रहण (hold) करता है तो यह रिट उसके विरुद्ध जारी होती है।

आयरलैंड

Taken from  
Ireland

← राज्य के नीति निर्देशक तत्व → (DRSP)  
(Directive principles of state policy)

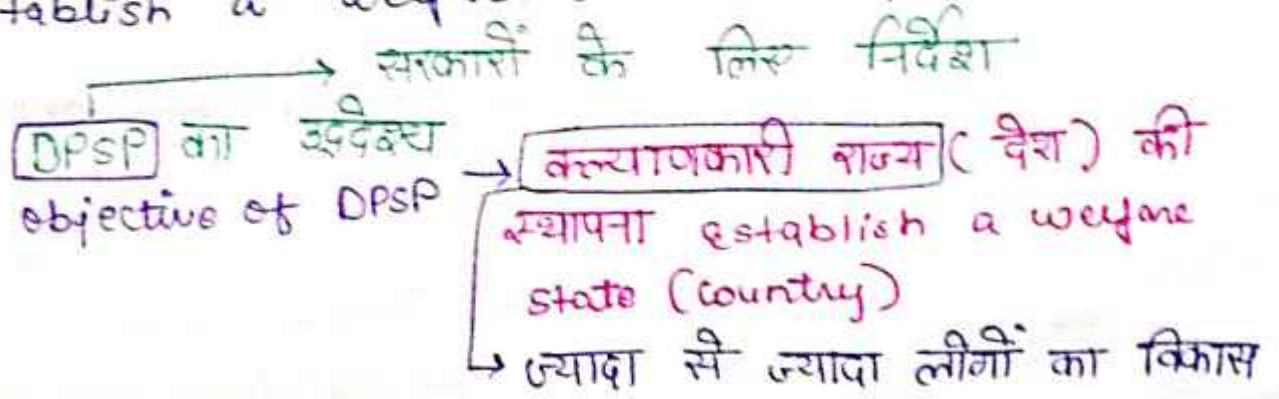
→ Part-IV, Art. 36-51  
(भाग)

- भारतीय संविधान के भाग-4, अनुच्छेद-36 से 51 तक में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' का वर्णन किया गया है।
- इसे 'आयरलैंड' के संविधान से लिया गया है।
- Part-4, Article 36 to 51 of the Indian constitution describe the 'Directive principles of state policy'.
- It has been taken from the constitution of Ireland.

Art-36 - राज्य की परिभाषा  
Definition of state

## Rojar with Ankit

- भारतीय संविधान नियमांशों का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।
- The aim of the Indian Constitution makers was to establish a welfare state in India.



अनुच्छेद-37 में कहा गया है कि "इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू (En-forced) नहीं कराया जा सकता है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

Art. 37 - states that "The provisions of this part can't be enforced by any court; it shall be the duty of the state to use these elements in law-making."

F.R. → court से लागू (enforced)

Art. 37 ⇒ DPSP को court से लागू नहीं कराया जा सकता है।

## Rojar with Ankit

अनुच्छेद - 38 - राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके

Art. 38 - Directs the state to promote public welfare and strive to establish a social order in which social, economic and political justice is assured to every individual.

Art. 38 → कल्याणकारी (welfare) → न्याय (justice)  
③ Political (राजनीतिक) ① सामाजिक (social)  
② आर्थिक (economic)

राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, अनु. 39 (घ)

The state shall provide equal pay for equal work to every citizen, whether male or female, Article 39 (d)

Art. 39(d) → Male (पुरुष) } समान कार्य के समान  
Female (महिला) } वेतन equal pay for  
equal payment

Art. 39 (A) ⇒ add on / जोड़ा गया ⇒ 42 (A) 1976

→ समान न्याय और नि: शुल्क विधिक सहायता  
equal justice and free legal aid

## Rojar with Ankit

अनुच्छेद-40 के तहत यह प्रावधान किया गया है  
राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठायेगा।

Art. 40 provides that the state shall take steps  
to constitute Gram panchayats.

Art. 40 → पंचायतों का गठन

⇒ संविधान संशोधन (Constitution Amendment)

⇒ ग्राम पंचायतों की स्थापना ⇒ Part (भाग) → IX  
↓  
73(A) 1992

⇒ Art. 243-2430, Schedule (अनुसूची) - II

अनुच्छेद-41 - सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार  
रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा,  
बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक  
सहायता प्राप्त कर सकें।

Art. 41 - All citizens have the right to employment  
and education according to their abilities and to  
receive public assistance in case of unemployment  
old age, sickness and disability.

Art. 41 → योग्यता (Qualification) ⇒ रोजगार  
⇒ शिक्षा (education) (employment)

⇒ बेरोजगारों को रोजगार

## Rojar with Ankit

अनुच्छेद - 42 - राज्य रखा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों की अपनी अनुकूल और मानवीयता अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

Art. 42 - The state shall endeavour to ensure that people are required to work in suitable and humane conditions and shall make provisions for maternity relief to woman.

Art. 42 → व्यक्ति → कीर्ति कार्य करवाना है  
उसके अनुसार ←  
जैसे व्यक्ति करने में सक्षम।

अनुच्छेद - 43 - राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन दे।

Art. 43 - The state should encourage cottage industries on individual or co-operative basis.

Art. 43 ⇒ कुटीर उद्योग  
Cottage Industries } Rural Area

अनुच्छेद - 43 (ख) - राज्य सहकारी समितियों के स्विच्छक गठन

अनुच्छेद 43 (ख) - सन्तानलैवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया है।

## Rojar with Ankit

Art. 43 B - Voluntary formation of state cooperative societies.

Art. 43 B - Added by the 97<sup>th</sup> constitutional Amendment Act 2011.

Art. 43 (B)  $\Rightarrow$  Add en  $\Rightarrow$  97(A) 2011  
 $\hookrightarrow$  सहकारी समितियों का गठन (formed by cooperative societies)

ex  $\Rightarrow$  डैयरी उद्योग (Dairy industries)

अनु. 44 - सामान्य नागरिक संहिता

Art. 44 - Uniform civil code